दैनिक शुभ भास्कर

सीधा सच से सामना......

उप्र व मप्र से प्रकाशित

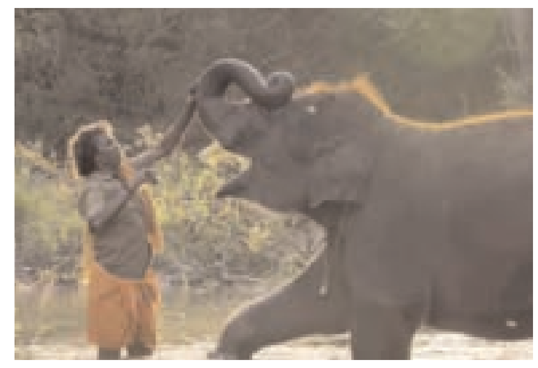

RNI : UPHIN/2015/64737 dailyshubhbhaskar@gmail.com

वर्ष -15 अंक- 139 | झांसी 01/गुरुवार/जून /2023 | पृष्ठ -8 मूल्य -03 रूपये

अजमेर में बोले प्रधानमंत्री

रिमोट कंट्रोल से चल रही थी कांग्रेस सरकार, सीमा पर सड़क बनाने से डरती थी

नयी दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। अपने सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अजमेर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी का यह दौरा राजस्थान में आगामी चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है। भाजपा राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने अभियान तेज कर चुकी है। मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए देश के लोगों को कर्तव्य पथ की दिशा दिखाने के लिए देवी अहिल्या जी को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आज भारत में नव निर्माण का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली छव। सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए हैं। भाजपा सरकार के ये 9 साल देशवासियों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं।कांग्रेस पर निशानाप्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेस पर भी जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी? पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी हुई थी। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। बड़े-बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपरपावर थी, कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। लेकिन आपने 2014 में अपने एक वोट से सब कुछ बदल दिया। पूरी दुनिया अब भारत के विकास की बात कर रही है। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है- गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। राजस्थान के लोगों ने भी इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया है।मोदी ने कहा कि आज देखिए, पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। ये कांग्रेस ही है जो श्वन रैंक वन पेंशनश् के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। भाजपा सरकार ने ना सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में, भाजपा सरकार ने 9 करोड़ लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन दिए हैं। इस संख्या को पूरा करने में कांग्रेस सरकार को 20 साल लग जाते। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे, वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी, जो देश के विकास को खाए जा रही थी। भ्रष्टाचार के बहाने कांग्रेस पर प्रहारमोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है तो उसमें से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस, हर योजना में 85: कमीशन खाने वाली पार्टी है।

शांति बहाल करने की कोशिश में जुटे अमित शाह, विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात जारी

नयी दिल्ली।

मणिपुर हिंसा ने एक बार फिर से देश की चिंता बढ़ा दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर दौरे पर हैं। वह लगाता विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे हैं। वह लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील कर रहे। मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा में 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमावर्ती शहर मोरेह का दौरा किया और सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के अलावा कुकी नागरिक समाज समूहों से मुलाकात की। उन्होंने मोरेह में रहने वाले तमिल व्यापारियों सहित विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। अमित शाह ने सोमवार रात मणिपुर पहुंचने के तुरंत बाद, मैतेई-कुकी जातीय हिंसा के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि और नौकरियों सहित एक मुआवजे के पैकेज को मंजूरी दी और बढ़ती कीमतों की जांच के लिए राज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का आदेश दिया। अमित शाह ने मंगलवार को विभिन्न मेइती और कुकी समूहों से मुलाकात की, जिन्होंने शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वे संकटग्रस्त राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम करेंगे।मणिपुर में शांति सर्वोच्च प्राथमिकताकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मणिपुर में शांति और समृद्धि है और उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया है।

साक्षी मर्डर कैस में पुलिस ने रिक्रिएट करवाया सीन, नया वीडियो भी आया सामने

दिल्ली के शाहबाद डेरी हत्याकांड को लेकर हर कोई दुखी है। हत्या के मुख्य आरोपी साहिल को पकड़ा जा चुका है। आरोपी ने बर्बर्ता की हदों को पार करते हुए इस हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने 31 मई को आरोपी साहिल का मेडिकल टेस्ट करवाया है। इस टेस्ट को करवाए जाने से पहले सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस की टीम साहिल को लेकर घटना स्थल पर पहुंची जहां उसने साक्षी का कत्ल किया था। इस दौरान पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और साहिल से कई सवाल भी पूछे। पुलिस पूछताछ में पता करने की कोशिश कर रही है कि साहिल ने नाबालिग लड़की के आने का इंतजार क्यों किया था।नया वीडियो फुटेज आया सामनेदिल्ली मर्डर मामले में नया फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये फुटेज नाबालिग युवती की हत्या से दो मिनट पहले का है। इस वीडियो में युवती उस जगह जाती हुई दिख रही है जहां साहिल ने उसकी हत्या की थी। हालांकि इस वीडियो में साहिल उसके साथ नजर नहीं आ रहा है।पिता को थी साहिल की जानकारीअब तक आए बयानों में मृतका की मां लगातार बोलती रही कि वो साहिल के संबंध में कुछ नहीं जानती थी। वहीं अब मृतका के पिता ने बताया है कि वो साहिल को जानते थे। ये जानकारी पुलिस को दर्ज एफआईआर से सामने आई है। पिता ने कबूल किया है कि वो जानते थे कि साहिल और उनकी बेटी एक दूसरे को एक वर्ष से जानते थे। पिता ने बताया कि जब भी उसे साहिल से दूर रहने की हिदायत की जाती थी तो वो घर में लड़कर घर छोड़कर चली जाती थी।साहिल को 1 जून को किया जाएगा कोर्ट में पेशजानकारी के मुताबिक साहिल को पुलिस ने 31 मई तक के लिए रिमांड पर रखा है। उसे आगे पूछताछ करने के लिए फिर से 1 जून को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि साहिल लगातार बयान बदल रहा है। पुलिस के मुताबिक साहिल ने स्वीकार किया है कि उसने हरिद्वार से चाकू खरीदा था। बता दें कि पुलिस को अबतक हत्या में उपयोग किया गया चाकू बरामद नहीं हुआ है। इसकी भी पड़ताल पुलिस कर रही है।

मोदी के बल पर ये हमारी बेटियों का अपमान कर रहे, बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर बोले अधीर रंजन चौधरी

पहलवानों ने 30 मई को डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफकार्रवाई नहीं करने पर अपने पदक हरिद्वार में विसर्जित करने की धमकी दी, लेकिन किसान नेताओं के हस्तक्षेप के बाद इसके खिलाफजाने का फैसला किया। जिसके बाद आज भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर उन पर लगे आरोप साबित होते हैं तो वह फांसी लगा लेंगे। अब पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफसे भी बयान समाने आया है। डब्ल्यूएफआईप्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनके पीछे सरकार, सत्तारुढ़ पार्टी और मोदी का बल है। मोदी के बल पर इन्होंने हमारी मां और बहनों के साथ जो यौन शोषण किया है, उसकी परवाह नहीं करते। हमारी बहन-बेटियां वैश्विक मंच पर ताकत दिखाकर हमारे देश को गौरान्वित करते हैं...आज जब उन बेटियों ने बेइज्जती के कारण आंदोलन छेड़ा, तब बेइज्जत करने वालों का पक्ष लेकर और सभी शिकायतों की धज्जियां उड़ाते हुए ये हमारी बेटियों का अपमान कर रहे हैं।रेसलिंग फेडरेशन ऑफइंडिया (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने बारांबकी में कहा कि मैंने कहा था कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वयं फांसी पर लटक जाऊंगा। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए वो मेरी फांसी चाहते हैं लेकिन सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो वो (पहलवान) अपना मेडल लेकर गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों गंगा में मेडल बहाने से बृज भूषण को फांसी नहीं मिलेगी।

पहलवानों के समर्थन में ममता बनर्जी ने निकाली रैली, कहा- इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर तीन दिन संसद भवन के उद्घाटन के वक्त मार्च करने की कोशिश करने पर पहलवानों के साथ कथित मारपीट के विरोध में बुधवार को सड़कों पर उतरीं। विश्व कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में हाजरा से रवींद्र सदन तक एक रैली निकालते हुए कहा कि हमें अपने पहलवानों पर गर्व है।पहलवानों के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाजरा मोड़ से रवींद्र सदन तक रैली निकाली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी एक टीम पहलवानों से मुलाकात करने जाएगी और उन्हें समर्थन देगी। हम आपके साथ हैं इसलिए आज हमने यह रैली निकाली है। कल भी इसे जारी रखा जाएगा। पहलवान हमारे देश के गौरव हैं। आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं।इससे पहले डब्ल्यूएफआईप्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनके पीछे सरकार, सत्तारुढ़ पार्टी और मोदी का बल है। मोदी के बल पर इन्होंने हमारी मां और बहनों के साथ जो यौन शोषण किया है, उसकी परवाह नहीं करते। हमारी बहन-बेटियां वैश्विक मंच पर ताकत दिखाकर हमारे देश को गौरान्वित करते हैं...आज जब उन बेटियों ने बेइज्जती के कारण आंदोलन छेड़ा, तब बेइज्जत करने वालों का पक्ष लेकर और सभी शिकायतों की धज्जियां उड़ाते हुए ये हमारी बेटियों का अपमान कर रहे हैं।

महाकाल लोक में अब स्थापित की जाएगी नई प्रतिमाएं, ज्योतिष आचार्यों के विरोध के बाद हुआ फैसला

मध्य प्रदेश।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल लोक गलियारा इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, रविवार को तेज आंधी-तूफान के चलते गलियारे में स्थापित रविवार को तेज आंधी-तूफान के चलते गलियारे में स्थापित गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। सरकार ने इन क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं को ठीक कर के फिर से स्थापित करने का फैसला लिया था, जिसे ज्योतिष आचार्यों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब गलियारे में पुरानी की बजाय नई प्रतिमाएं स्थापित करने का फैसला किया है।

सभी गारंटियों को लागू करेंगे, मंत्रियों के साथ बैठक के बाद बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया

नयी दिल्ली।

कांग्रेस ने पहली कैबिनेट बैठक में चुनावों के दौरान घोषित पांच श्गारंटियोंश् को लागू करने का वादा किया था। सरकार ने योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में प्री-कैबिनेट बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार ने सभी पांच चुनावी गारंटी को लागू करने का फैसला किया है...आज प्री कैबिनेट बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, इसे कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। 2 जून को होने वाली महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को विधान सौध में मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की और कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में घोषित पांच श्गारंटियोंश् को लागू करने के तरीकों पर चर्चा की। मंत्रियों ने लोकसभा चुनाव से पहले श्गारंटियोंश् को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्रियों ने कथित तौर पर सीएम को श्गारंटियोंश् को लागू करने पर निर्णय लेने की शक्ति भी दी।

कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम घोषित, 62.06 फीसदी विद्यार्थी सफल हुए

बिहार।

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (ठैम्ठ) ने बुधवार को साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। जो लोग कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने अंक चेक करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस साल इंटर की कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 56,435 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कुल 56,061 छात्रों के लिए परिणाम तैयार किया गया है, क्योंकि 376 विद्यार्थी स्क्रूटिनी के तहत पास हुए हैं। कुल 34,792 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिससे उत्तीर्ण प्रतिशत 62.06 प्रतिशत हो गया है। आर्ट्स स्ट्रीम में पास प्रतिशत 63.51 प्रतिशत और कॉमर्स में 71.65 प्रतिशत है। साइंस में छात्रों का पास प्रतिशत 60.46 फीसदी रहा है। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य इंटर परीक्षा में दो विषयों तक सफल नहीं हुए थे।

अश्विनी वैष्णव का दावा, मोदी सरकार में रेलवे की बदली तस्वीर, लोगों को मिल रही सुविधाएं

नयी दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में उनके सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने लोगों के जीवन को बदला है। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री लगातार अपने-अपने विभागों के कामकाज का भी ब्यौरा दे रहे हैं। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफतौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में रेलवे की तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी है। रेलवे की तस्वीर बदलीअश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने कहा कि आप रेलवे स्टेशनों पर जाइए, वे साफ-सुथरे हैं, ट्रेनें समय पर चल रही हैं, सभी शौचालयों को बायो-टॉयलेट में बदल दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यदि आप पिछले 60 वर्षों को देखें, तो लगभग 30,000 किमी विद्युतीकृत थे। पिछले नौ वर्षों में, 40,000 किमी विद्युतीकरण किया जा रहा है। नौ साल पहले हर दिन 3.5-4 किमी नई पटरियां बिछाई जाती थीं, आज यह संख्या 14 किमी प्रतिदिन है, जो सालाना 5,000 किमी है।रेलवे को गति मिली रेल मंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में अगर हम तुलना करें तो भारतीय रेलवे में स्विट्जरलैंड का पूरा नेटवर्क जुड़ गया है।

भारत के कड़े रुख को जानता है मगर फिर भी मानता नहीं है पाकिस्तान

नयी दिल्ली।

पाकिस्तान है कि मानता नहीं। उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं लेकिन वह फिर भी गलत कामों से बाज नहीं आता। सीमा पार से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के प्रयास में पाकिस्तान आतंकवादियों या ड्रोनों के माध्यम से कभी इनकी खेप पंजाब सीमा पर भेजता है तो कभी जम्मू-कश्मीर में, लेकिन सतर्क सुरक्षा बल उसके हर प्रयास को विफल कर देते हैं। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को आज तब बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब नियंत्रण रेखा (एलओसी) के नजदीक सीमा पर लगी बाड़ के पास जवानों ने हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा प्रयास विफल कर इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।अधिकारियों ने बताया कि गुलपुर सेक्टर के करमारा गांव में तड़के हुई गोलीबारी में सेना का एक जवान और गिरफ्तार आरोपियों में से एक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सीमा पर तैनात सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियों का एहसास होने पर उन लोगों को रोकने की कोशिश की जिसके बाद वहां गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके की तुरंत घेराबंदी की गई और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक घायल है। गिरफ्तार किये गये लोगों के पास से मादक पदार्थ और हथियारों की खेप बरामद की गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुई शर्मनाक हरकत, बांटे गए कंडोम और गर्भनिरोधक टैबलेट, मचा बवाल

मध्यप्रदेश।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामूहिक विवाह करने वाले दुल्हा और दुल्हन को उपहार दिए जाते है। इस योजना के तहत थांदला शहर में 29 मई को 296 जोड़ों का विवाह करवाया गया है। इस समारोह में दूल्हनों को उपहार के तौर पर मेकअप बॉक्स दिया गया है। वहीं इस मेकअप बॉक्स को लेकर अब हंगामा शुरू हो गया है।

दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक झाबुआ जिले के थांदला में हुए सामूहिक विवाह समारोह में मेकअप बॉक्स में गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम होने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मिलने वाले इन उपहारों में गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम होने के मामले में काफी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को शर्मनाक करार दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे जागरुकता का नाम दे रही है।सामूहिक रूप से परिणय सूत्र में बंधे नवविवाहित जोड़ों को अधिकारियों ने मेकअप बॉक्स में गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम बांट दिए। इसे लेकर शिकायत भी की गई है। वहीं घटना के बाद विभाग के अधिकारी भी मामले की लिपापोती कर एक दूसरे पर इस गलती को मढ़ने में लगे हुए है। स्वास्थ्य विभाग पर जिला अधिकारी ने आरोप लगाया और कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने परिवार नियोजन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम के तहत कंडोम और गर्भनिरोधक बांटे थे।बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय मदद देने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की शुरुआत हुई थी।

मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की मस्जिद समिति की याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में 12 सितंबर, 2022 को वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल दायर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 की याचिका को खारिज कर दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में दायर हिंदू उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की गई थी। पिछले साल दिसंबर में जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दोनों पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।गौरतलब है कि मस्जिद समिति ने अक्टूबर 2022 में उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके कुछ दिनों बाद वाराणसी कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

सड़क सुरक्षा की मेडिकल कालेज हुआ आयोजन

उरई

उरई-प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग एवं महानिदेशक, उपाम, उत्तर प्रदेश शासन एल0 वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, सड़क सुरक्षा व दुर्घटनाओं में मानवीय आर्थिक एवं सामाजिक क्षति की रोकथाम हेतु राजकीय मेडिकल कालेज में लोक संवाद का आयोजन किया गया।

शासन की मंशानुरूप प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग एवं महानिदेशक, उपाम, उत्तर प्रदेश शासन एल0 वेंकटेश्वर लू ने सम्बोधित करते हुये कहा कि अधिकारी, छात्र-छात्रायें, जनमानस सड़क सुरक्षा नियम जीवन में संस्कार की तरह आत्मसात करने की आवश्यकता हैं। उन्होने संविधान व गीता आदि का सन्दर्भ देते हुये कर्मयोगी बनने के लिये चार मूलमंत्र जैसे गीताज्ञान, सड़क सुरक्षा मानव रक्षा, विश्व रक्षा का सन्देश देते हुये प्रदेश में दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने पर बल दिया। उन्होने बताया कि मन और विवेक को काबू में रखकर वाहन चलाना चाहिये तथा क्रोध व नींद की दशा में वाहन का संचालन न करें। उन्होने कहा कि अपने स्वप्रेरणा से नियमों का पालन करना चाहिये न कि चालन के भय से, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये गम्भीर है समय-समय पर परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा अभियान चलाकर प्रेरित किया जाता हैं। उन्होने कर्मयोग के माध्यम से सड़क दुर्घटना में कमी लाने की अपील की। उन्होने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज समृद्ध बनता हैं साथ ही समाज में फैली नकारात्मकता कम होगी क्योंकि जब इस तरह के कार्यक्रमों में युवा पीढ़ि भाग लेती है तो उनके अन्दर नयी सोच व भावना उत्पन्न होती है उसी के आधार पर वह एक नये समाज की संरचना तैयार करते हैं। उन्होने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के मुख्य उद्देश्य बताते हुये कहा कि इस योजना से छात्रों कसे आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, नीट जैसी प्रतियोगिताओं के लिये मुफ्त कोचिंग प्रदान करना हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के होनहार छात्रों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा और वह अच्छी कोचिंग प्राप्त करके सफल हो सकेगे।जिला पंचायत अध्यक्ष डा0 घनश्याम अनुरागी, विधायक माधौगढ़ मूलचन्द्र निरंजन, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के उपनिदेशक एस0एन0 त्रिपाठी, सड़क सुरक्षा के डिप्टी कमिश्नर मयंक ज्योति, मिशन कर्मयोगी वक्ता आचार्य रामकृष्ण गोस्वामी, कपिल आनन्द चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना में मानवीय, आर्थिक एव सामाजिक क्षति की रोकथाम के लिये लोक संवाद आदि विषयों पर प्रकाश डाला।जिलाधिकारी चाँदनी सिंह ने कर्मयोग, अभ्युदय योजना एवं सड़क सुरक्षा लोक संवाद में समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डा0 अभय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी न्यायिक मोतीलाल यादव, नगर मजिस्ट्रेट रामप्रकाश, परियोजना निदेशक शिवाकान्त द्विवेदी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार, उप शिक्षा निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ भगवत पटेल, ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन सौरभ कुमार, ए0आर0टी0ओ0 प्रवर्तन विनय कुमार पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पण्डित, बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार, समाज कल्याण अधिकारी प्रवीन कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी विकास सत्यम त्रिपाठी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

युवाओं में बढ़ती नशे की लत को सामूदायिक भागीदारी से रोकना होगा .संभागीय आयुक्त

उदयपुर दैनिक शुभ भास्कर सुनील कुमार

बद्री निरोगी राजस्थान अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे विश्व तंबाकू निषेध दिवस दिनांक 25 मई से 31 मई तक 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन रविंद्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला प्रदर्शनी एवं रैली का आयोजन किया गया ।

तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया द्य विश्व तंबाकू निषेध दिवस को साप्ताहिक रूप से मनाने के लिए 25 मई 2023 से 31 मई 2023 तक अलग.अलग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों में तंबाकू मुक्त रहने के लिए जन जागरूकता फैलाई गई द्य तम्बाकू मुक्तए तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं आरएनटी मेडिकल कॉलेज के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई द्य कार्यशाला को संबोधित करते हुए संभागीय आयुक्त महोदय ने बताया कि युवाओं में दिनों दिन नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है और यह काम अपने घर से करना चाहिए ।

जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि किसी भी विषय कार्यक्रम पर को वर्ष में 1 दिवस मनाया जाता है उसके पीछे मंशा यह रहती है कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने लिए हमें आगे आने पड़ेगा द्य इसी तरह विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष पर मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि नशे में परिवार व समाज आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है तंबाकू सेवन से कई तरह की बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं जिसमें कैंसर मुख्य हैं तंबाकू उत्पाद से हमें दूर रहना चाहिए।

संयुक्त निदेशक डा अजेडण् एण् काजी ने बताया कि बिना लक्ष्य निर्धारित किए तंबाकू निषेध कार्यक्रम की सफलता संभव नहीं है अतः सभी को अपने आसपास कम से कम दो व्यक्तियों को तंबाकू से मुक्ति दिलाने का संकल्प लेना होगा तभी यह कार्यक्रम सफल हो सकता है ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर बामनिया ने तंबाकू निषेध के लिए विभाग द्वारा चलाए गए पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया । पूरे वर्ष कोटपा एक्ट के तहत हुई कार्यवाही एवं चालान का ब्यौरा प्रस्तुत किया । तंबाकू निषेध दिवस हेतु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें नर्सिंग के छात्रों ने पेंटिंग के माध्यम से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारियाँ दीं। छात्रों द्वारा रंगोली के माध्यम से भी संदेश दिया गया ।

डॉक्टर बामणिया ने बताया कि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के बाद 1 जून से 31 जुलाई तक 2 माह तक टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत गतिविधियां शुरू की जाएगी उक्त गतिविधियों में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर विभिन्न स्तर पर कार्यशाला जैस जनप्रतिनिधियों ए स्टेकहोल्डर्स की कार्यशाला तथा अंतर विभागीय कोआर्डिनेशन के साथ.साथ तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्था शिक्षा संस्थान आंगनवाड़ी केंद्र को किया जाएगा

जागरूकता रैली का आयोजन

ए सीएमएचओ डा बामनिया ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज ने संयुक्त रूप से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया जिसे संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेडण् ए़ काज़ीए आर एन टी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डा विपिन माथुरएसी एम एच ओ डा शंकर बामनियाए सी एम एच ओ 2 डॉ पलातए अधीक्षक डॉ आर एल सुमन ने हरी झंडी दिखाई । रैली में नर्सिंग स्टूडेंट एवं आशा सहयोगिनियों ने भाग लिया । रैली के माध्यम से बैनर एपोस्टर और नारों द्वारा लोगों का जागरूक किया गया।

जिले के सभी खंड स्तरों पर भी रैली और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तंबाकू के दुष्प्रभाव बताए गए और तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए शपथ दिलाई गई ।

कार्यशाला में संभागीय आयुक्त ए जिला कलेक्टर एजिला पुलिस अधीक्षकए संयुक्त निदेशक ;चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्धमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एमहाराणा भोपाल अस्पताल अधीक्षक एवं कॉलेज के प्रिंसिपल ने सहित विभाग एव कॉलेज के 500 ज्यादा स्टूडेंट्स आशाए चिकित्स्क उपस्थित रहे ।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रतिदिन की भांति पुलिस कार्यालयए महोबा में जनतादर्शन में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश.

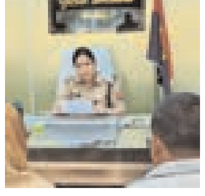

महोबा पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालयए महोबा में जनसुनवाई की गईए इस दौरान फरियादियोंध्जनसामान्य की समस्याओं को एक.एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए गएए जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्कालए निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय.समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा.निर्देश दिये गये।

महिला कल्याण ,बाल पुष्टाहार विभाग का जिलाधिकारी ने फीता काटा

उरई

उरई-राज्यमंत्री, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उ. प्र. प्रतिभा शुक्ला व जिलाधिकारी चाँदनी सिंह के कर कमलों द्वारा ने कलेक्ट्रेट परिसर में सखी वन स्टॉप सेंटर का फीता काटकर उद्घघाटन किया।

जनपद जालौन को पीड़ित महिलाओं को समस्त सुविधाएं एक छत के नीचे दिए दी जाएंगी। जनपद को सखी वन स्टॉप सेंटर के रूप में मिला तोहफा अब पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा बल्कि उन्हें सखी वन स्टॉप सेंटर में ठहरने, परामर्श सुविधा, विधिक परामर्श की सुविधा तथा अन्य समस्त सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। इस केंद्र पर पीड़ित महिला के साथ साथ उनके बच्चे के भी ठहरने की व्यवस्था है, इस केंद्र के माध्यम से पीड़िता को भोजन परामर्श मेडिकल सुविधा तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पूनम निगम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ0 अमरेंद्र पौत्स्यायन सहित आदि मौजूद रहे।

ट्रक से ई-रिक्शा उतारते समय 11000 विधुत लाइन की चपेट में आने से नाबालिग की मौत

शिकायती पत्र में मृतक के पिता ने लगाए गंभीर आरोप

पनवाड़ी/महोबा

दैनिक शुभ भास्कर ब्यूरो समीर खान

कस्बे के बुड़ेरा रोड स्तिथ ई-रिक्शा एजेंसी में ट्रक में लदे ई-रिक्शा उतारते समय 11000 की विधुत लाइन में रिक्सा टच होने के परिणाम स्वरुप युवक के झुलस जाने पर आनन फानन सी.एच.सी पनवाड़ी ले गए वहां डाक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक का पंचनामा कर पी.एम. को जिला मुख्यालय भेजा मृतक के पिता ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में एजेंसी स्वामी पर कार्यवाही की माँग

बताते चलें आज प्रातरू कस्बे के बुड़ेरा रोड स्तिथ ई-रिक्शा एजेंसी पर पनवाड़ी निवासी साहिल मंसूरी पुत्र सहीद मंसूरी उम्र 16 बर्ष एजेंसी में मजदूरी कार्य करता था आज बाहर से आए ट्रक में लदे ई-रिक्शा उतारने को लेकर एजेंसी स्वामी ने एजेंसी से अवकाश पर रहने के बाबजूद मजदूर साहिल को घर से बुलाने पहुंची पिता का आरोप है कि साहिल को नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए एजेंसी स्वामी साहिल को घर से एजेंसी ले गई आरोप है कि ट्रक में लदे ई-रिक्शाओं को उतारने पर बाध्य किया गया साहिल के ई-रिक्शा उतारते समय ट्रक के ऊपर से निकली 11000 बिधुत लाइन में रिक्शा छुलने के परिणाम स्वरुप बिधुत करंट से साहिल बुरी तरह झुलस गया जिसे आनन फानन सी.एच.सी पनवाड़ी लेकर आए जहाँ डॉक्टरों ने चेकअप कर मृत घोषित कर दिया वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर पी.एम. को मुख्यालय भेजा मृतक के पिता सहीद द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में एजेंसी स्वामी के ऊपर लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में दूरभाष पर थाना प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार पाण्डेय से पूंछा तो उन्होने बताया मृतक के पिता सहीद मंसूरी द्वारा दिए गए शिकायती पत्र मेरे संज्ञान में आया है जाँच कर उचित कार्यवाही की जाएगी वहीं अकस्मिक साहिल की मौत पर परिवार जनों में कोहराम मच गया महिलाओं का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रतिदिन की भांति पुलिस कार्यालय महोबा में जनतादर्शन में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश.

महोबा।

पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालयए महोबा में जनसुनवाई की गईए इस दौरान फरियादियोंध्जनसामान्य की समस्याओं को एक.एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए गएए जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्कालए निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय.समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा.निर्देश दिये गये।

सीएम हेल्पलाइन नोट अटेंड पाई गई शिकायतों के लिए अधिकारियों पर लगा जुर्माना

निवाड़ी

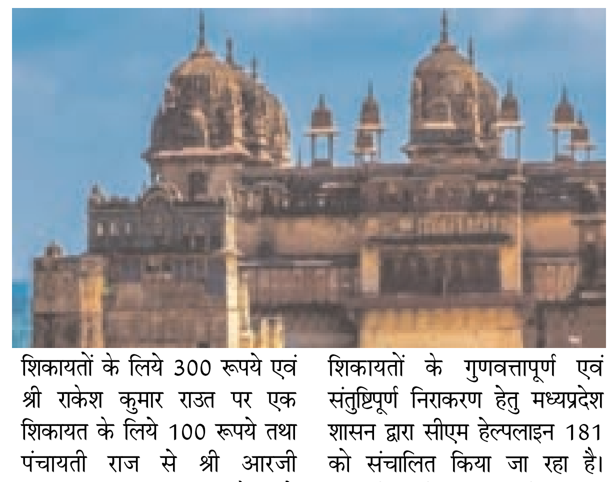

कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर माह मई 2023 में नॉट अटेण्ड पाई गई शिकायतें जिनके निराकरण एल.1ध्एल.2 स्तर द्वारा समय सीमा में नहीं किये जाने एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप प्रति शिकायत 100 रूण् के मान से जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

तदनुसार खनिज विभाग से श्री अजय मिश्रा पर 4 शिकायतों के लिये 400 रूपयेए संस्थागत वित्त विभाग से श्री एसपी समाधिया पर 5 शिकायतों के लिये 500 रूपयेए पशुपालन एवं डेयरी विभाग से डॉण् केएम राजपूत पर एक शिकायत के लिये 100 रूपयेए नगरीय विकास एवं आवास विभाग से श्री महेश नापित पर एक शिकायत के लिये 100 रूपयेध्श्री आरएस अवस्थी पर दो शिकायत के लिये 200 रूपये एवं श्री विजय बहादुर सिंह पर दो शिकायत के लिये 200 रूपयेए उर्जा विभाग से श्री प्रदीप निरंजन पर तीन शिकायतों के लिये 300 रूपये एवं श्री राकेश कुमार राउत पर एक शिकायत के लिये 100 रूपये तथा पंचायती राज से श्री आरजी अहिरवार पर एक शिकात के लिये 100 रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

उक्त अर्थदण्ड की राशि 3 दिवस में कलेक्ट्रेट कार्यालय ;जिला सैनिक कल्याण निवाड़ी के कार्यालय में जमा करते हुये रसीद प्राप्त कर पावती लोकसेवा प्रबंधन को जमा करायें। साथ ही आदेशित किया गया है कि शिकायतों के नॉट अटेण्ड होने की पुनरावृत्ति न हो।

ज्ञातव्य है कि सुशासन के निर्देशों के अंतर्गत नागरिकों की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 को संचालित किया जा रहा है। जिसकी समीक्षा मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन द्वारा समाधान ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्येक माह की जाती है। सीएम हेल्पलाइन 181 पोर्टल पर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में एल.1ध्एल.2 अधिकारियों का मुख्य उत्तरदायित्व रहता है। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण के संबंध में लोकसेवा प्रबंधन विभाग द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है साथ ही समय.समय पर निर्देश भी जारी किया गये हैं।

थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 31ण्05ण्2023 को अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम एवं क्षेत्राधिकारी नगर रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवाली व कां0 प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तलाशध्चेकिंग वाँछितध्वारण्टी के दौरान वारण्टी अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र अयोध्या सिंह निवासी ग्राम रतौली थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश ;कोर्ट नण् 2द्धविशेष न्यायाधीश ;एससीण्एस एक्टद्ध के द्वारा जारी वाद संख्या 46/19 धारा 452/354/323504ध्506 व 3 ;1द्धदए धध्3 ;2द्ध5कध्3 ;1द्ध व ;1द्धै ब्ैज् ।बज के वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त राहुल सिंह को थानाक्षेत्र के ग्राम रतौली से नियमानुसार गिरफ्तार किया गयाए बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

'न्यायालय से सजा मिलने के बाद सरपंच को पद से हटाए जाने की मांग'

निवाड़ी।जनपद पंचायत क्षेत्र पृथ्वीपुर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिनोनिया खास के सरपंच को न्यायालय से सजा मिलने के बाद पद से हटाए जाने की मांग का आवेदन बीते रोज ग्राम के निवासी दीपक नायक द्वारा जनसुनवाई में दिया गया।ग्राम सिनोनिया खास के निवासी दीपक नायक द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया की ग्राम पंचायत सिनोनियाखास मैं वर्तमान में अशोक कुमार कुशवाहा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं जिनको न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायधीश निवाड़ी श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव के द्वारा प्रकरण क्रमांक 33ध्2017 मध्य प्रदेश राज्य बनाम छक्कीलाल कुशवाहा एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24 8 2022 के अनुसार धारा 8 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के आरोप में दोषी पाए जाने पर 6 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।जिसके बाद ग्राम पंचायत सिनोनिया खास तहसील निवाड़ी के सरपंच अशोक कुमार कुशवाहा को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के उपरांत सरपंच पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है जिसके चलते ग्राम पंचायत के सरपंच अशोक कुमार कुशवाहा को ग्राम पंचायत सिनोनिया खास के सरपंच पद से हटाया जाना लोकहित में वांछनीय है। दीपक नायक द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि अशोक कुमार कुशवाहा को धारा 36 39 एवं 40 मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की विधि के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत सिनोनियाखास के सरपंच का पद धारण किए जाने योग्य नहीं है इसलिए विधि के उक्त प्रावधानों के आधार पर ग्राम पंचायत के सरपंच को पद से तत्काल हटाया जाए।

शाह सतनाम जी छात्र महाविद्यालय में वार्षिक एलुमनाई मीट का आयोजन

सिरसा।।।(सतीश बंसल) शाह सतनाम जी छात्र महाविद्यालय में आईक्यूएसी के तत्वावधान में एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में अब तक के पासआउट विद्यार्थियों ने महाविद्यालय से जुड़ी अपनी यादों व अनुभवों को सांझा किया।सभी ने कहा कि यहीं से ही शिक्षा और उच्च संस्कार प्राप्त करके हम सब अपने जीवन में सफल हो पाए हैं।यहां के पूर्व विद्यार्थी देश की नामचीन कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन हैं।इससे पहले कार्यक्रम की शुरूआत में महाविद्यालय के प्रिंसीपल डा. दिलावर सिंह व शाह सतनाम जी बॉयज कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेजिडेंट सुनील इन्सां ने सभी पुराने विद्यार्थियों का स्वागत किया और अपना कीमती समय देने के लिए उनका शुक्रिया किया व सभी विद्यार्थियों को भविष्य में कॉलेज से जुड़े रहने और उनके उज्जवल भवष्य के लिए शुभकामनायें दी।इस मौके पर एसोसिएशन के वाईस प्रेजिडेंट संदीप कुमार, सेक्रेटरी हरप्रीत सिंह सेठी, कैशियर सतीश कुमार वएसोसिएशन के सदस्य सुनील कुमार, अमरदीप सिंह, सतप्रीत इन्सां, अमित और रोहित भी मौजूद रहे।एसोसिएशन की तरफसे विद्यार्थियों के लिए गेम्स, सम्मान पुरस्कार और भोजन का विशेष प्रबंध किया गया।एलुमनाई मीट के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा देश-विदेश में बैठे सभी पूर्व विद्यार्थियों को गूगल मीट एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर दिया गया।जिसके पश्चात सभी विद्यार्थियों ने निर्धारित समय पर ऑनलाइन व ऑफलाइन जुड़ कर अपने विचार सांझा किये।अंत में कॉलेज प्रिंसिपल डा. दिलावर सिंह इन्सां व एसोसिएशन के प्रेजिडेंट सुनील इन्सां ने सभी पूर्व विद्यार्थियों को अगले वर्ष होने वाले पूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह में महाविद्यालय में आने का निमंत्रण दिया।

नवकीरत गिल ने शूटिंग में जीता सिल्वर पदक

सिरसा।।।(सतीश बंसल) श्री कृष्णा स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी हिसार द्वारा 27 से 30 मई तक आयोजित छठी श्री कृष्णा स्पोर्ट्स शूटिंग चौंपियनशिप-2023 में जोरबा शूटिंग एकेडमी के होनहार शूटर नवकीरत गिल ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए सिल्वर पदक पर निशाना साधा।एकेडमी के संचालक अमित फुटेला ने बताया कि 27 से 30 मई तक हिसार में आयोजित इस प्रतियोगिता में एकेडमी की ओर से नवकीरत गिल के अलावा कई अन्य शूटरों किंजल, बलराम, मिष्ठी सेठी, अवतार, अनुज, विक्रम, रविंद्र, विकास, नवकीरत ने भी प्रतिभागिता की। उन्होंने बताया कि नवकीरत गिल ने 10 मीटर राइफल में अपने सटीक निशाने से सिल्वर मैडल प्राप्त करने के साथ-साथ 15 हजार नगद पुरस्कार भी हासिल किया।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी है बड़े भाई मनोज रेजारू डॉ. संदीप सरावगी

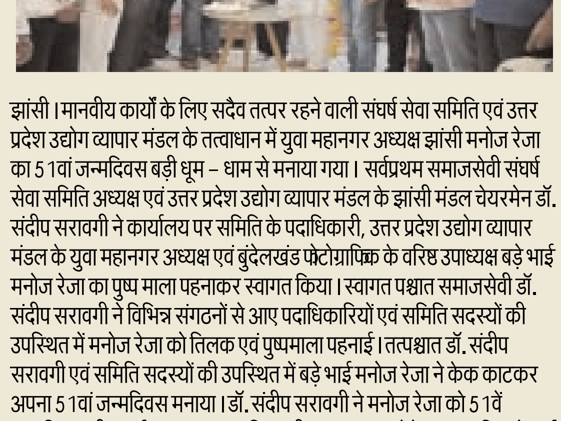

झांसी।मानवीय कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहने वाली संघर्ष सेवा समिति एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में युवा महानगर अध्यक्ष झांसी मनोज रेजा का 51वां जन्मदिवस बड़ी धूम - धाम से मनाया गया। सर्वप्रथम समाजसेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के झांसी मंडल चेयरमेन डॉ. संदीप सरावगी ने कार्यालय पर समिति के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के युवा महानगर अध्यक्ष एवं बुंदेलखंड फोटोग्राफिक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई मनोज रेजा का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया।स्वागत पश्चात समाजसेवी डॉ. संदीप सरावगी ने विभिन्न संगठनों से आए पदाधिकारियों एवं समिति सदस्यों की उपस्थित में मनोज रेजा को तिलक एवं पुष्पमाला पहनाई।तत्पश्चात डॉ. संदीप सरावगी एवं समिति सदस्यों की उपस्थित में बड़े भाई मनोज रेजा ने केक काटकर अपना 51वां जन्मदिवस मनाया।डॉ. संदीप सरावगी ने मनोज रेजा को 51वें जन्मदिवस की बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बड़े भाई मनोज रेजा बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इन्होंने अपने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एवं संघर्ष सेवा समिति को नई दशा व दिशा दी है।हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हम सभी को मार्ग दिखाते रहेंगे।हम सभी इनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं इस अवसर पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से कविता लेखक एवं लोकगीत गायक मुन्ना मासूम ने अपनी कविता के माध्यम से मनोज रेजा को जन्मदिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।इस मौके पर संघर्ष सेवा समिति जिलाध्यक्ष (ग्रामीण) इं. विनोद वर्मा, बसंत गुप्ता, राजू सेन, राकेश अहिरवार, सुशांत गेंडा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजनारायण मिश्रा, हिंदू जागरण मंच से जिलाध्यक्ष जयदीप खरे, उत्तम सिंह (पूर्व सरपंच), सुशांत गेंडा, बसंत गुप्ता, भूपेंद्र यादव, भगवान दास वर्मा, राजू सेन, मीना मसीह, हाजरा रब, नीलू रायकवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

दैनिक शुभ भास्कर

चिंतन

कश्मीर न आकर पाक-चीन ने मुंह की खाई

हमेशा कश्मीर का राग अलापने वाले पाक और उसकी हां में हां मिलाने वाले चीन को भारत ने एक ही दांव में चित कर दिया। चीन-पाक ने कश्मीर में होने वाली जी-20 कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक में हिस्सा न लेने का ऐलान करके अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की नापाक कोशिश की थी, लेकिन उनके सारे प्रयास धराशायी हो गए। उनका साथ दे रहे तुर्किये को भी मुंह की खानी पड़ी। श्रीनगर में जी-20 के पर्यटन कार्यसमूह का सम्मेलन होना इसका परिचायक है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी अन्य देश की आपत्ति सहन करने को तैयार नहीं करता। भारत ने न केवल पाकिस्तान, चीन की आपत्ति को दरकिनार किया बल्कि इन दोनों देशों को दो टूक जवाब भी दिया। ऐसा करना आवश्यक था, क्योंकि भारत को अपने किसी भी भूभाग में इस तरह के आयोजन करने का अधिकार है, वे चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ही क्यों न हों। चीन-पाक के विरोध के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर के 122 प्रतिनिधियों ने पर्यटन समूह की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का इसलिए भी महत्व बढ़ गया था, क्योंकि कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद यह पहला ऐसा आयोजन था, जिसमें पूरी दुनिया के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। पाक-चीन इससे दूर रहने का ऐलान करके फिर से कश्मीर को हवा देने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जिस तरह से कार्यक्रम में विदेशी मेहमान पहुंचे उससे एक बात तो साफ हो गई कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय मानता है कि जम्मू-कश्मीर से विभाजनकारी अनुच्छेद 370 खत्म करने का भारत का निर्णय सही था। पहले भी चीन कश्मीर के मामले में अपनी फजीहत पहले भी करा चुका है। उसने पाकिस्तानी आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से प्रतिबंधित करने की पहल में हर बार अड़ंगा लगाया, लेकिन कई मौकों पर उसे मुंह की खानी पड़ी। चीन अपनी हरकतों से यही बता रहा कि आतंकवाद के मामले में उसकी कथनी-करनी में अंतर है। यह अंतर दुनिया भी देख रही है, लेकिन चीन सही रास्ते पर आने को तैयार नहीं। उसने अरुणाचल प्रदेश में भी जी-20 की एक बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन भारत अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसे आगे भी न केवल ऐसा करना चाहिए, बल्कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। भारत को उसके समक्ष यह साफ करना भी आवश्यक है कि तिब्बत और हांगकांग उसकी दुखती रग है। उसको इसी रग को दबाना चाहिए। भारत सरकार ने भी कश्मीर के श्रीनगर में जी-20 से जुड़े आयोजन को भव्य रूप देने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया को बदलते जम्मू-कश्मीर को देखने का अवसर मिलेगा। इससे पाक-चीन का वह मंसूबा नाकाम हो गया, जिसमें वे कश्मीर के बारे में बेहूदी बातें करके भारत को बदनाम करने की कोशिशें करते आ रहे थे। इसके अलावा दोनों देशों को विश्व मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत का भी आभास होगा। वह सभी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, उससे यही पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका किस कदर बढ़ रही है। इसका एक प्रमाण अभी हाल में हिरोशिमा में जी-7 की बैठक में मिला और फिर पापुआ न्यू गिनी में भी। भारतीय प्रधानमंत्री जिस तरह जापानी मीडिया में छाए रहे, उसी तरह पापुआ न्यू गिनी और फिजी में भी। जिस तरह सिडनी में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी इज द बॉस। उससे पाक-चीन को समझ जाना चाहिए कि अब भारत बदल चुका है, जो किसी के दबाव में नहीं आने वाला।

सारा संसार

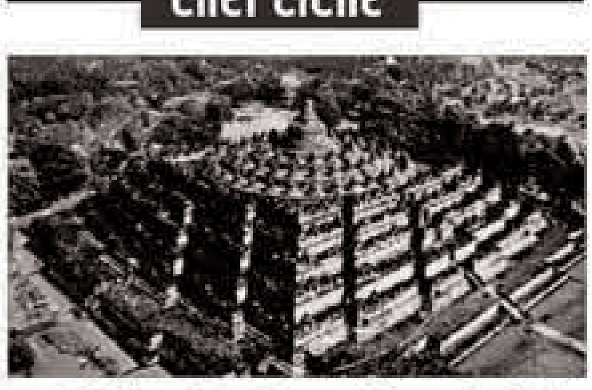

जावा, इंडोनेशिया स्थित बोरोबुदुर मंदिर, 9 शताब्दी के महायान बौद्ध मंदिर है. यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है।

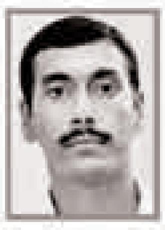

रवि शंकर

किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब उसके नागरिक सेहतमंद हों। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च बढ़ाया जाना एक जरूरत बन चुकी है, जहां प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य खर्च बेहद कम है। स्वास्थ्य सेवा पर भारत का सार्वजनिक व्यय वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.1 प्रतिशत है, जबकि जापान, कनाडा और फ्रांस अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कहा गया है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाकर 2025 तक जीडीपी के 2.5 फीसदी के बराबर करने की जरूरत है।

स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनानी होंगी

किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब उसके नागरिक सेहतमंद हों, लेकिन भारत में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बहुत सम्मानजनक नहीं है। यहां की सरकार को अपनी 143 करोड़ आबादी की सेहत का ख्याल रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार इसके लिए हर साल स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपये का बजट पेश करती है, मगर आज भी देश की स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। महामारी ने नया नजरिया दिया है। इस लिहाज से स्वास्थ्य सेक्टर पर अधिक खर्च और अधिक बजट की उम्मीद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रही है, मगर भारत जैसे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च बढ़ाया जाना एक जरूरत बन चुकी है, जहां प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य खर्च बेहद कम है। स्वास्थ्य सेवा पर भारत का सार्वजनिक व्यय वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.1 प्रतिशत है, जबकि जापान, कनाडा और फ्रांस अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कहा गया है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए केंद्र व राज्यों का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय धीरे- धीरे बढ़ाकर 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 फीसदी के बराबर करने की जरूरत है। मालूम हो, वित्त वर्ष 2023 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य के लिए कुल वित्तीय आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.1 प्रतिशत रखा गया है। वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमान में 2.2 प्रतिशत था।

स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और इनकी गुणवत्ता (एचएक्यू) मामले में भारत 145वें स्थान पर है। लैंसेट के अध्ययन के अनुसार, भारत 195 देशों की सूची में अपने पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी पीछे है। 'ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिजीज' अध्ययन में हालांकि कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और गुणवत्ता मामले में वर्ष 1990 के बाद से भारत की स्थिति में सुधार देखे गए हैं। भारत सूची में चीन (48), श्रीलंका (71), बांग्लादेश (133) और भूटान (134) से भी नीचे है, जबकि स्वास्थ्य सूची (हेल्थ इंडेक्स) में भारत का स्थान नेपाल (149), पाकिस्तान (154) और अफगानिस्तान (191) से बेहतर है। बहरहाल, सरकार के सामने देश की विशाल व विविधता भरी जनसंख्या को सस्ता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति का खर्चा दिन- प्रतिदिन बढ़ रहा है और बुनियादी ढांचे की कमी बहुत ज्यादा है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 18,99,228 अस्पताल के बिस्तर होने का अनुमान है और अगर देखा जाए तो प्रति 1,000 जनसंख्या पर लगभग 1.4 बिस्तर उपलब्ध हैं। दूसरे देशों की बात की जाए तो चीन में बेड का अनुपात 1000 पर चार से अधिक है। श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड राज्यों में प्रति 1,000 पर लगभग तीन हैं और थाईलैंड और ब्राजील में अस्पताल के बिस्तर प्रति 1,000 पर दो से अधिक हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये

आंकड़ा 1000 की जनसंख्या पर कम से कम 5 होना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों के भारी भरकम बिल भरने की वजह से भारत में हर साल करीब छह करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ऐसे लोग इलाज के लिए भारी कर्ज लेते हैं। इसका प्रमुख कारण भारत के लोगों की सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं होना है और इसका एकमात्र समाधान पर्याप्त संख्या में लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराना है। देश के स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में लगातार उदारीकरण के बावजूद, देश की कुल आबादी के पांचवें हिस्से से भी कम जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा के दायरे में है। इसके कई कारण है। खैर, ऐसे में विश्व बैंक की उस रिपोर्ट पर विचार करने की जरूरत है, जिसमें कहा गया है कि 90 फीसदी बीमारियों की पहचान की जा सकती है और इसे ठीक भी किया जा सकता है। अफसोस है कि किसी ने इस सुझाव पर गंभीरता से विचार नहीं किया। अफसोस ये है कि कोई भी सरकार आए, तात्कालिक समस्याओं का समाधान खोजने में समय गंवा देती है। किसी भी देश का विकास योग्य और स्वस्थ मानव संसाधन पर निर्भर करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिससे मानव संसाधन को बेहतर बनाया जा सकता है। अमर्त्य सेन का कहना है कि उदारीकरण के लिए चाहे जितने भी सेक्टर खोल दें, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र है, जिसे हर हाल में सरकारी क्षेत्र में ही होने चाहिए। कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है, पर भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में बिना अधिक पैसे खर्च किए आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। भारत की मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अनेक प्रकार की विसंगतियों एवं विषमताओं से परिपूर्ण है। यह विडंबना तब है जब भारत में इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी जरूरी कार्यक्रम और नीतियां मौजूद हैं, लेकिन इन्हें सही तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की घोषणा और क्रियान्वयन से यह आस जगी थी कि अस्वस्थ भारत की तस्वीर बदल जाएगी परंतु ऐसा नहीं हुआ।

भारत की करीब तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, पर जानकर यह आश्चर्य होता है कि भारत अपनी कुल जीडीपी का केवल 2 फीसदी हिस्सा ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, जो 143 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का वैश्विक स्तर 6 फीसदी माना गया है, लेकिन नई स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 2.5 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। 6 फीसदी का आंकड़ा कब भारत हासिल करेगा कोई प्रस्तावित वर्ष नहीं बताया गया है। साफ है, स्वास्थ्य शायद भारत के राजनीतिक एजेंडा के में प्राथमिकता कभी नहीं रहा। यदि हम चीन और भारत के आर्थिक विकास की तुलना करें, तो चीन के आर्थिक विकास का कारण उसका स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश करना रहा है। भारत को भी नागरिकों को विश्व की स्पर्धा में आगे लाने के लिए उन्हें स्वास्थ्य-उपहार देना होगा।

2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब कार्यकाल संभाला तब उनको स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के निरंतर खराब प्रदर्शन से दो-चार होना पड़ा। उनको यह पहले ही पता था कि भारत की तरक्की तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए। बहरहाल, दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहे भारत में हेल्थ सेक्टर की बुनियाद ही कमजोर है। ऐसे में सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी आसान पहुंच हो और कम खर्च में इलाज हो सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

क्षमा करें और भूल जाएं

संकलित

दर्शन

जीवन में हमें कई बार चुनौतियों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में हमारा किसी न किसी ऐसी घटना से साक्षात्कार होता है, जो हमें पसंद नहीं होती या जिसके कारण हमें दुख होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारा किसी तरह अनुचित किया हो, शब्दों से हमें भावनात्मक रूप से दुख पहुंचाया हो या शारीरिक कष्ट पहुंचाया हो। परिणाम यह होता है कि हम निराश, दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते, तब तक हमारे साथ क्या होता है? हम हमेशा उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं या किसी और से भी उन बातों को दोहराते रहते हैं। कुछ लोग जिनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, वे शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं या अपना क्रोध किसी और पर निकालते हैं। ऐसा होने पर हम अपने चारों ओर नकारात्मक वातावरण पैदा कर लेते हैं। अपने मन की शांति खो देते हैं। कुछ क्षणों में घटित हुई घटना के लिए हम अपने जीवन के तमाम घंटे इस बात में लगा देते हैं कि उसका बदला कैसे लें। यदि हम इसके बजाय क्षमा कर दें तो हम इस समय का शांतिपूर्वक सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपना ध्यान उस ओर लगाएं, जो आध्यात्मिक रूप से मददगार हो। जैसे कि पिता-परमेश्वर को याद करना, ध्यान-अभ्यास करना, निष्काम सेवा करना और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना। आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान-अभ्यास में सफलता अपने मन को स्थिर करके अंतर में ध्यान टिकाने पर निर्भर है।

हमारे पास कोई सिद्धि है तो घमंड न करें

संकलित

प्रेरणा

स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस अपने उपदेश, सीधे-सादे स्वभाव और रहन-सहन की वजह से काफी प्रसिद्ध थे। रोज ही उनसे मिलने कई लोग आते थे। प्रसिद्ध होने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला और वे हमेशा आनंद में रहा करते थे। एक दिन वे अपने दैनिक काम कर रहे थे। कुछ लोग उनके सामने बैठे हुए थे और परमहंस का काम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उन्हें अच्छी बातें सुनने को मिल सके। उस समय वहां एक बड़े संत पहुंच गए। संत का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सभी उनका सम्मान करते थे। वे परमहंस जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन परमहंस जी अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने संत की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखकर संत को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मैं पानी पर चलकर आया हूं। मेरे पास चमत्कारी सिद्धि है, जिससे मैं बिना डूबे पानी पर धरती की तरह चल सकता हूं। मुझे ये चमत्कार करते हुए लोगों ने देखा है। तुम मुझे ठीक से देख भी नहीं रहे हो और न ही बात कर रहे हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भैया, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं और आपके पास सिद्धि भी है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सिद्धि है और इतना छोटा काम किया है। नदी पार करनी थी तो नाव वाले को दो पैसे दे देते, वह आपको आराम से नदी पार करवा देता। जो काम दो पैसे में हो सकता है, उसके लिए आपने इतनी तपस्या की है।

सटाका

आज की पाती

नदियों को स्वच्छ रखना जरूरी

अक्सर यह भी देखा गया है कि धार्मिक आयोजनों में उपयोग की जाने वाली सामग्री या सामान को लोग धार्मिक आयोजन के संपूर्ण होने के बाद या तो किसी पानी की नहर में या फिर नदी में फेंक देते हैं। कुछ लोग तो सूखी हुई नहर में ही वह सामग्री डाल देते हैं, फिर वह क्या पाप हुआ या पुण्य? लोग गंगा नदी के किनारे जाते हैं पुण्य कमाने, लेकिन गंगा में पॉलीथीन या अन्य गंदगी डालने से भी परहेज नहीं करते। हमारा फर्ज है कि हम नदियों को स्वच्छ रखें।

– रविंद्र सक्सेना, दुर्ग

ट्रेंड

पूर्व चेतावनी प्रणाली ईजाद हो

मौसम संबंधी आपदाओं से अधिक नुकसान में वृद्धि हुई है, लेकिन बेहतर चेतावनियों और आपदा प्रबंधन के चलते इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या में कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र इस वक्त पर रहा है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली जल्द हो।

-एंटोनियो गुटेरेस, यूएन महासचिव

हम हैरान हैं

राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन के लोग जिस तरह बचाव कर रहे हैं और आपने क्या हासिल किया है, वह पूरी दुनिया के लिए देखने का विषय है। मैं अमेरिका के लिए बोलता हूं जब मैं कहता हूं कि आपने अब तक जो कुछ किया है उससे हम हैरान हैं।

-जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति

सत्यनिष्ठ रहें

यथार्थवादी एवं सत्यनिष्ठ रहें। हर परिस्थिति में सर्वोच्च सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लक्ष्य विहीन मन ही दुख, संताप और अवसाद का स्रोत है। सभी प्राणी के लिए लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें व आध्यात्मिक प्रकाश को संचित प्राप्त करें।

-अवधेशानंद, आध्यात्मिक गुरु

विचार

पंकज चतुर्वेदी

सिकुड़ती समुद्री तट चिंताजनक

केंद्र सरकार के वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर) की एक ताजा रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि देश की समुद्री सीमा कटाव और अन्य कारणों के चलते सिकुड़ रही है और यह गंभीर पर्यावरणीय, सामाजिक, आजीविका के संकटों की जननी है। अकेले तमिलनाडु में राज्य के कुल समुद्र किनारे का कोई 42.7 हिस्सा संकुचन का शिकार हो चुका है। हालांकि कोई 235.85 किलोमीटर की तट रेखा का विस्तार भी हुआ है। जब समुद्र के किनारे कटते हैं तो उसके किनारे रहने वाले मछुआरों, किसानों और बस्तियों पर अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। सबसे चिंता की बात यह है कि समुद्र से जहां नदियों का मिलन हो रहा है, वहां कटाव अधिक है और इससे नदियों की सेहत और बिगड़ सकती है। ओडिशा के छह जिलों बालासोर, भद्रक, गंजम, जगतसिंहपुर, पुरी और केन्द्रपाड़ा के लगभग 480 किलोमीटर समुद्र रेखा पर भी कटाव का संकट गहरा गया है। ओडिशा जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2021-2030 में बताया गया है कि राज्य में 36.9 फीसदी समुद्र किनारे तेजी से समुद्र में टूटकर गिर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ केरल द्वारा किए शोध में बताया गया है कि त्रिवेन्द्रम जिले में पोदियार और अचुथेंग के बीच के 58 किलोमीटर के समुद्री तट का 2.62 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बीते 14 सालों में सागर की गहराई में समा गया। यह शोध बताता है की वर्ष 2027 तक कटाव की रफ्तार भयावह हो सकती है। वैसे इस शोध में एक बात और पता चली कि इसी अवधि में समुद्र के बहाव ने 700 मीटर नई धरती भी बनाई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाले चेन्नई स्थित नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के आंकड़े बताते हैं की देश की कुल 6907 किलोमीटर की समुद्री तट सीमा है और बीते 28 सालों के दौरान हर जगह कुछ न कुछ क्षतिग्रस्त हुई ही है। देश में सर्वाधिक समुद्री तटीय क्षेत्र गुजरात में 1945.60 किमी है और यहां 537.50 किमी कटाव दर्ज किया गया है, आन्ध्र प्रदेश के कुल 1027.58 किमी में से 294.89, तमिलनाडु में 991.47 में से 422.94 किमी में कटाव देखा जा रहा है। पुडुचेरी जो कभी सबसे सुंदर समुद्र तटों के लिए विख्यात था, धीरे-धीरे अपने किनारों को खो रहा है। कोस्टल रिसर्च सेंटर ने देश में ऐसी 98 स्थानों को चिन्हित किया है जहां कटाव तेजी से है इनमें से सबसे ज्यादा और चिंताजनक 28 स्थान तमिलनाडु में हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 16 और आंध्र में 07 खतरनाक कटाव वाले स्थान हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में तहत बनाए गए सीआरजेड में समुद्र में आए ज्वार की अधिकतम सीमा से 500 मीटर और भाटे के बीच के क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया गया है। इसमें समुद्र, खाड़ी, उसमें मिलने आ रहे नदी के प्रवाह को भी शामिल किया गया है। ज्वार यानि समुद्र की लहरों की अधिकतम सीमा के 500 मीटर क्षेत्र को पर्यावरणीय संवेदनशील घोषित कर इसे एनडीजेड यानि नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया। इसे सीआरजेड-1 भी कहा गया। वर्ष 1998 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्र तट क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और इसकी राज्य इकाइयों का भी गठन किया, ताकि सीआरजेड कानून को लागू किया जा सके, लेकिन ये सभी कागज पर ही रह गए।

करंट अफेयर

गलत रास्ता चुना तो देश के लिए भयावह होगा: पित्रोदा

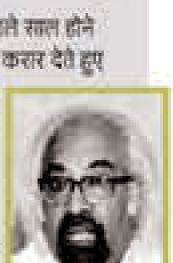

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को भारत के लिए मील का पत्थर करार देते हुए कहा है कि 2024 में अगर 'गलत रास्ता' चुन लिया गया तो यह देश के लिए भयावह होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 12 महीनों तक भारतीय-अमेरिकी लोगों को मेहनत करनी होगी और बोलने का साहस दिखाना होगा। पित्रोदा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के उपलक्ष्य में शिकागो में इस सप्ताह जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए भारतीय-अमेरिकी लोगों के एक समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें लंबा सफर तय करना है। कम से कम अगले 12 महीनों तक खाली मत बैठिए। आपको कड़ी मेहनत करनी है। आपको अगले आम चुनाव के बारे में हर छोटी बात के बारे में चिंता करनी है क्योंकि यह चुनाव भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।' पित्रोदा ने कहा, अगले चुनाव में चुनने के लिए दो रास्ते हैं। अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया है तो आप खत्म हैं।

ऑफ बीट

घर जलवायु परिवर्तन में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं

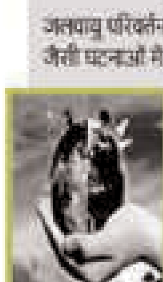

जलवायु परिवर्तन की वजह से पहले से ही अधिक गर्मी और आग लगने जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, और यह आशंका है कि सूखा तथा अत्यधिक वर्षा जैसी दोनों स्थितियां भीषण हो जाएंगी। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु के लिहाज से अधिक अनुकूल घरों की आवश्यकता है। हमें गर्मी में ठंडक बनाए रखने के साथ-साथ विपरीत मौसम, हवा, बारिश, कीड़ों और धुएं से बचने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता होगी। ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जो कठोर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो, जिससे ऊर्जा बचाने में मदद मिले और जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो ताकि जलवायु परिवर्तन की स्थिति और खराब न हो। गर्म होती जलवायु में अपने घरों को ठंडा रखने की रणनीतियों को जलवायु क्षेत्रों की विविधता के प्रति संवेदनशील रखे जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मिल्डुरा और मेलबर्न जैसे शहरों में घरों को इमारतों में उच्च स्तर के तापावरोधन और खिड़कियों पर प्रभावी छायाकृतियों के संयोजन से अत्यधिक गर्मी से बचाया जा सकता है।

दैनिक शुभ भास्कर

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न

मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आहूत की गई।

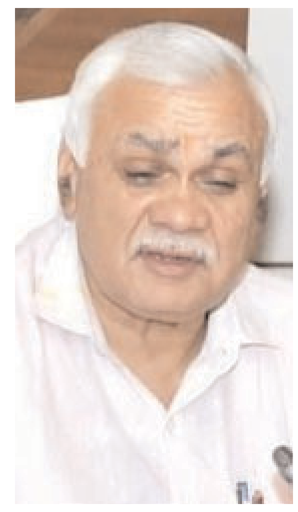

झाँसी। शुभभास्कर

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' से पात्र किसानों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से 'ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्तीकरण अभियान' चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिये जिलाधिकारी प्रतिदिन स्वयं सघन समीक्षा करें। अभियान का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाये, ताकि अधिक से अधिक इस अभियान का फायदा उठा सकें। कैम्प के लिये जिन कर्मियों की रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाई गई है, वह अनिवार्य रूप से कैम्प में उपस्थित रहें। शिविर में प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि मोबाइल एप से ई-केवाईसी के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाये। बैठक में बताया गया कि कुल निर्धारित 67,070 शिविरों के सापेक्ष 32,670 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।

'स्वामित्व योजना' की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया से मानचित्र प्राप्त होने के उपरान्त पड़ताल की कार्यवाही अगस्त, 2023 तक पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अतः सर्वे ऑफइंडिया से मैंप प्राप्त होने पर पड़ताल की कार्यवाही तेजी से पूर्ण करायी जाये। इसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया से अवशेष नक्शों को प्राप्त करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरन्तर संवाद बनाये रखा जाये।

बैठक में बताया गया कि 90,894 गांवों का ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त 72,916 ग्राम के मानचित्र-1 के सापेक्ष 60,090 गांवों में स्थानीय पड़ताल के पश्चात मानचित्रों को सर्वे ऑफ इंडिया को वापस किया जा चुका है। 39,460 गांवों की 56,95,109 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। स्वामित्व योजना के समग्र कार्य के अन्तर्गत जनपदों की रैंकिंग में ललितपुर, जालौन, झांसी, मुरादाबाद ने 99 प्रतिशत अंक से अधिक अंक प्राप्त किये हैं।

उन्होंने बताया कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा 'आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के चयन' की कार्यवाही पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिये पोर्टल तैयार कराया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मेरिट के आधार पर चयन कर भरी जायेंगी। अवशेष 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जायेंगी। डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन सहित पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं से पदों को भरने के लिये 45-60 दिनों में चयन की कार्यवाही पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय चयन समिति का गठन समय से करा लिया जाये। आरक्षण के साथ रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर अपडेट करा दिया जाये। आवेदन भरने में लोगों को असुविधा न हो, इसके लिये कॉमन सर्विस सेण्टर के कर्मियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करा दी जाये। 'प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएम-एफएमई) योजना' की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिये केन्द्र सरकार द्वारा उन सभी लोगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रहा है, जो लोग खाद्य उद्योग में अपना काम शुरू करना चाहते या अपनी यूनिट को अपग्रेड करना चाहते हैं। इस योजना में अब तक सर्वाधिक ऋण मिर्जापुर, वाराणसी, सुल्तानपुर, अयोध्या, चन्दौली, बलिया, अमेठी, गोरखपुर, फतेहपुर, भदोही द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम-एफएमई योजना का जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये और स्वयं सहायता समूह और फूड प्रोसेसिंग में कार्य करने वाले लोगों को चिन्हित कर इस योजना का लाभ लेने के लिये प्रेरित किया जाये। डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में भी इस योजना की समीक्षा कर इस योजना के तहत अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत कराया जाये। इसके अलावा बैंक द्वारा अस्वीकृत होने वाले आवेदनों की भी अलग से समीक्षा की जाये। इससे जनपद में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में 43,252 ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिये खुले में शौच मुक्त ग्राम (ओ0डी0एफ0) की स्थिरता को बनाये रखा जाये। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण से राज्य, जनपद व ग्राम की रैंकिंग का निर्धारण होता है, अतः सभी जनपदों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जाये। जिन जनपदों द्वार चयनित ग्रामों की कार्ययोजना अभी तक पंचायती राज विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गई है, 7 जून तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाये, जिससे बारिश से पूर्व कार्य आरम्भ कराया जा सके। उन्होंने कहा कि गोबरधन योजना के अन्तर्गत 17 जनपदों के 22 प्लांट, जिनमें कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, उसे शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाये। बैठक में बताया गया कि गोबरधन योजना के अन्तर्गत 20 जनपदों में 32 प्लांट का निर्माण पूर्ण हो चुका है, 38 जनपद में 60 प्लांट निर्माणाधीन हैं।

उन्होंने कहा कि 'भारत सरकार के रेलवे, रोड, फ्रेट कारिडोर, एयरपोर्ट आदि परियोजना' प्रदेश के विकास से जुड़े हैं। इन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये भूमि अधिग्रहण सहित अन्य लम्बित प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण किया जाये। जनपद अथवा मण्डल स्तर पर निस्तारण संभव न होने पर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाये। कहीं भी किसी भी स्तर पर विलंब नहीं होना चाहिये। मा0 न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करते हुये उनका निराकरण कराया जाये। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी बलरामपुर व जिलाधिकारी कासगंज द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण की प्रशंसा करते हुये कहा कि कनवर्जेन्स के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराने का बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे गांव में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, इस तरह के प्रयास अन्य जनपदों को भी करना चाहिये। योजना बनाते समय उसकी सस्टेनेबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाये। इसके अलावा गांव में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये भी प्रयास करें, जिससे लोगों को रोजगार के लिये गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

इससे पूर्व जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा ''माँ पाटेश्वरी विला सिटी'' पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने बताया कि शहरी सुविधाओं से युक्त इस सिटी का निर्माण कनवर्जेन्स के माध्यम से बाढ़ प्रभावित कल्याणपुर ग्राम के परिवारों के लिये किया गया है। इस सिटी की चहारदीवारी कराने के साथ-साथ कॉलोनी में जल एवं विद्युत संयोजन, शौचालय, नरेगा पार्क, ड्रेनज सिस्टम, कैटेल शेड आदि का निर्माण कराया गया है।

इसी क्रम में जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर ने ''नीली क्रान्ति (मत्स्य पालन) से आर्थिक समृद्धि का अभिनव प्रयास'' विषय प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने बताया कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये तालाबों को पट्टे पर आवंटित करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही तालाबों को पिकनिक स्पाट के रूप में विकसित किया गया है। इससे जनपद में रोजगार के साथ-साथ राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जिलाधिकारी कासगंज द्वारा ''जनपद कासगंज के आधुनिक गांव'' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने बताया जनपद में पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर 14 गांवों का चयन कर उनमें अत्याधुनिक सड़कें, मार्ग प्रकाश हेतु सोलर लाइट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, नाइट विजन के साथ सी0सी0टी0वी0 कैमरे, फ्री वाई-फाई, मिनी स्टेडियम, ओपन जिम, स्मार्ट क्लासेज आदि की सुविधायें विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें से 3 ग्रामों-नगला सेड्डू, भुजपुरा, धुवियाई में विकास

एमओयू को धरातल पर लाने के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के दिए निर्देश

इन्वेस्टर्स के साथ विभागीय अधिकारी संवाद स्थापित करते हुए इकाई के स्थापन हेतु प्राथमिकता से कार्य करना सुनिश्चित करें

ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को शामिल किए जाने के निर्देश, इन्वेस्टर्स की सभी समस्याओं को तत्काल दूर करें

फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण की शिथिल प्रगति पर सहायक निदेशक कारखाना, उपश्रमायुक्त को अलग से किया तलब

आरएम यूपीसीडा के बैठक में अनुपस्थित रहने तथा इन्वेस्टर फ्रेंडली कार्य न करने पर मुख्यालय स्तर पर पत्र लिखने के निर्देश दिए

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति - 2022 जनपद के इन्वेस्टर्स के लिए बेहद लाभप्रद, उद्यमी आगे आए

झाँसी। शुभभास्कर

जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में जिलास्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुये कहा कि इन्वेस्टर समिट में आए एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली निवेशकों की निवेश संबंधी समस्याओं का संबंधित विभाग तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास हेतु तत्परता से कार्य कर रही है, इन्वेस्टर्स समिट में बुंदेलखंड के निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। उससे बुंदेलखंड में निवेश की वृद्धि हेतु औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों का पूर्ण रूप से संबंधित विभागीय अधिकारी सहयोग करें।

जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित एक-एक इन्वेस्टर से संवाद स्थापित किया और इकाई के स्थापन हेतु आने वाली समस्याओं की जानकारी देते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इन्वेस्टर्स की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अनावश्यक रूप से पत्रावलीयों को रोके जाने पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में इन्वेस्टर्स फ्रेंडली माहौल का अधिक से अधिक उद्यमी लाभ उठाना सुनिश्चित करें। नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को नई उद्योग नीति के तहत शासन द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं की अथवा छूट संबंधित जानकारी मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक से अधिक उद्यमी क्षेत्र की ओर आकर्षित हों। उन्होंने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति नीति-2022 का जनपद में व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए, इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित उद्यमियों को प्रोत्साहन नीति का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। बैठक में एमओयू हस्ताक्षरित उद्यमियों की समस्याएं सुनते हुए जिलाधिकारी ने कहा की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरिमनी के लिए जनपद झांसी के लिए 90 इकाइयों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जबकि 265 एमओयू साइन किए गए हैं ग्राउंड सेरेमनी के लिए और इकाइयों को शॉर्टलिस्ट किए जाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग इन्वेस्टर्स की हर संभव मदद करते हुए उनके कार्यों को पूर्ण करें। मै0 पीतांबरा ग्रीन एन्वायरो वेंचर्स के पार्टनर श्री अनूप गर्ग द्वारा बायोमास कोल ब्रिकेट बनाने की इकाई स्थापित करने हेतु लगभग 05 एकड़ भूमि की आवश्यकता से अवगत कराया गया, जो तहसील मोंठ में स्थापित होगी जिससे पर पराली प्रबंधन में भी सहयोग प्राप्त होगा। जिलाधिकारी ने उक्त इकाई के स्थापन से क्षेत्र में पराली ना जलने से होने वाली लाभ की भी जानकारी दी और पूरा सहयोग दिए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने विकास भवन में आयोजित जिला उद्योग समिति की बैठक में कहा कि मा0मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बुन्देलखण्ड के चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई पर्यटन नीति और उद्योग नीति को तैयार किया गया है जिसके माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास हो। उन्होंने कहा कि अनेकों योजनायें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के नव सृजन हेतु संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को प्राप्त हो ताकि बुन्देलखण्ड में उद्योगों का सृजन हो और लोगों को रोजगार मिले। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का योजना की बिंदुवार जानकारी उद्यमियों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बैंकर्स अपने कार्यो की स्वयं समीक्षा करें और उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिलायें। ÷ निवेश मित्र योजना की समीक्षा करते हुये उन्होने निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित आनलाइन आवेदन पत्र पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम,जेडीए, यूपी सीडा व अन्य विभागों को तत्काल ऑनलाइन आवेदन पत्र को निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनपद की रैंकिंग आपके प्रपत्रों के निस्तारण न करने से प्रभावित हो रही है।

प्रमुख सचिव के मुख्य आतिथ्य में अभी अभ्युदय योजना, मिशन कर्मयोगी एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन संपन्न

'' लोकतंत्र व समाज को सशक्त करने के लिये सभी को समर्पित भाव और दृढ़ता से समाजहित में कार्य करना होगा

जिलाधिकारी के नेतृत्व में जनपद झांसी में संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन की प्रगति पर प्रमुख सचिव ने की भूरी-भूरी प्रशंसा

जीवन को सार्थक करने के लिये कर्म को कर्मयोग बनाना होगा साथ ही सात्विक प्रवृत्ति को भी बढ़ाना होगा

ट्रैफिक की समस्या के समाधान हेतु त्याग, संयम एवं अनुशासन प्रमुख कारक

शासन-प्रशासन के कार्यों में अपना योगदान प्रदान करते हुए राष्ट्रहित में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए

झाँसी। शुभभास्कर

प्रमुख सचिव परिवहन विभाग एवं महानिदेशक उपाम उत्तर प्रदेश शासन श्री एल वेंकटेश्वर लू (आई0ए0एस0) जी के मुख्य आतिथ्य में श्अभ्युदय योजना तथा मिशन कर्मयोगी एवं वर्ष 2023 में सड़क सुरक्षा तथा दुर्घटनाओं में मानवीय आर्थिक एवं सामाजिक क्षतिश् की रोकथाम हेतु श्लोक संवाद कार्यक्रमष् का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया।

लोक संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रमुख सचिव महोदय द्वारा अभ्युदय योजना की समीक्षा करते हुए कहा की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आवेदकों की संख्या और अधिक बढ़ाये जाने के लिये लोगों को मोटीवेट करें। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जनपद झांसी में संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन की प्रगति पर महोदय द्वारा जिला प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा की प्रशिक्षण में प्रशिक्षित अध्यापक है, साथ ही आईएएस तथा पीसीएस अधिकारी भी क्लास में प्रशिक्षण देते है, उनका सभी लाभ उठायें। प्रदेश में 18 मण्डलों में अभ्युदय योजना संचालित है और जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसे यू-ट्यूब पर अपलोड किया गया है उसे सभी इण्टर कालेजों में उपलब्ध कराये ताकि शुरु से ही बच्चों में आईएएस व आईपीएस बनने की इच्छा हो।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत सभी वर्गो के प्रतिभावान व मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निशुल्क प्रशिक्षण आनलाइन व क्लासरुम प्रशिक्षण की सुविधान्तर्गत आयोजित कार्यशाला में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन में व्यक्त करते हुए उन्होने कहा कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। उन्होने कहा कि लोकतंत्र व समाज को सशक्त करने के लिये सभी को समर्पित भाव और दृढ़ता से समाजहित में कार्य करना होगा तभी समाज विकसित होगा। जीवन को सार्थक करने के लिये कर्म को कर्मयोग बनाना होगा साथ ही सात्विक प्रवृत्ति को भी बढ़ाना होगा, तभी ज्ञान बढ़ेगा। अपने उदबोधन में उन्होने उपस्थित छात्र-छात्राओं से कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुये कार्य करें ताकि लक्ष्य की पूर्ति हो सके। उन्होने बताया कि अभ्युदय का आकार समग्र विकास सबसे योग्य लोग आगे आये।

अभ्युदय योजना की समीक्षा के अंतर्गत बताया गया कि जनपद झांसी में इस योजना के तहत कुल 242 छात्र पंजीकृत है जिसमें से 127 अभ्यर्थी यूपीएससी, यूपीपीएससी एवं लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु, 33 अभ्यर्थी नीट की परीक्षा हेतु, 54 अभ्यर्थी आईआईटी एवं जेईई की परीक्षा हेतु तथा 28 अभ्यर्थी एनडीए एवं सीडीएस सम्मिलित हैं।

जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान हेतु त्याग संयम एवं अनुशासन समस्या के निराकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कारक होते हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन प्रमुख कारकों का अनुसरण करना चाहिए एवं शासन-प्रशासन के कार्यों में अपना योगदान प्रदान करते हुए राष्ट्रहित में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक संभव प्रयास पूर्ण किए जाए तथा जनपद वासियों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन हेतु समय-समय पर जागरूक किया जाए तथा उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मानव जीवन के महत्व के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग पर स्थित चौराहों, तिराहों एवं जंक्शन पर जाम की स्थिति को रोकने हेतु इन जगहों पर बनाए जाने वाले सर्किल का निर्माण उपयोगिता के अनुरूप कराया जाए जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

प्रमुख सचिव परिवहन ने कहा कि ऑटो यूनियन के प्रतिनिधियों से संवाद कर टोकन सिस्टम के माध्यम से ऑटो चालकों को पैसेंजर बिठाने की व्यवस्था बनाने हेतु प्रेरित किया जाए, जिससे नगर के प्रमुख चौराहों पर खड़े होने वाले ऑटो पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हों सकें और ट्रैफिक जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। समीक्षा के दौरान सड़कों पर बार-बार होने वाले अतिक्रमण की समस्या के निराकरण हेतु उन्होंने कहा कि सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाने हेतु समय-समय पर अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए साथ ही ऐसे लोगों का चिन्हांकन किया जाए जो अतिक्रमण हटाने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर लेते हैं। इसके साथ ही सड़क मार्ग पर अवैध तरीके से वाहन पार्क करने वाले वाहन स्वामी का भी चालान किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने वाले लोगों की सूचना नगर के जिम्मेदार नागरिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर दर्ज करा कर ट्रैफिक की समस्याओं के निराकरण में जिला प्रशासन का सहयोग करें। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री जुनैद अहमद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश एस0, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री सुधाकर पाण्डेय, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या विभाग श्री एसएन त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट श्री अंकुर श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

खेत तालाब योजना हेतु आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ

झाँसी। शुभभास्कर

उप कृषि निदेशक श्री एम0पी0 सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग ;भूमि संरक्षण अनुभागद्ध को जनपद में खेत तालाब खुदवाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023.24 में जनपद को 1121 का लक्ष्य प्राप्त हुआ। जिसके लिए ऑनलाइन आवदेन की प्रक्रिया प्रारम्भ है योजना हेतु लाभार्थी का चयन ष्प्रथम आवकष् प्रथम पावक के अधार पर किया जाना है। वर्षा का जल जो खेतों से बहकर बाहर चला जाता है और साथ में उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता हैए को खेत में रोककर उसे खेत तालाब में इकट्ठा कर इस पानी का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यो में उपयोग के लिए बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना चालायी जा रही है योजना वर्ष 2016.17 से संचालित है और जनपद में संचालित चार भूमि संरक्षण इकाइयों के माध्यम से अभी तक चार हजार से अधिक खेत तालाब खोदे जा चुके है। उप कृषि निदेशक के द्वारा बताया गया कि योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय बेवसाइट पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल हतपबनसजनतमण्हवअण्पद पर पंजीकरण होना अनिवार्य है पंजीकरण ध् चयन हेतु पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर श्अनुदान पर खेत तालाब हेतु बुकिंग करे लिंक पर क्लिक करके कृषक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। कृषक भाइयों को पंजीकरण के उपरान्त मध्यम तालाब हेतु रू0 2000ध् तथा लघु तालाय हेतु रू0 1000ध् टोकन मनी जमा करना होगा टोकन मनी जगा होने की ऑनलाइन पुष्टि के बाद आगामी 15 दिन में कृषकों को खेत तालाब के निर्माण हेतु निर्धारित खेत की खैतानीए फेाटो तथा निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा कृषक भाइयों को यह ध्यान रखना होगा कि यदि 15 दिवस के अन्दर उनके द्वारा अभिलेख अपलोड नहीं किये जाते तो टोकन मनी जब्त कर प्रतीक्षा सूची से अगले कृषक को अवसर प्रदान किया जायेगा।उप कृषि निदेशक द्वारा यह भी बताया गया कि मध्यम तालाब का आकार 35मी0 ग् 03मी0 गहरा चौड़ा 03 मी0 गहरा होता है तथा लघु तालाब का आकार 22मी0 लंगा ग् 20मी0 चौड़ा ग 03मी0 गहरा होता है साथ ही तालाब में पानी अंदर आने के लिए एक पक्के इनलेट का भी निर्माण कराया जाता है तालाब खुदवाने हेतु कृषक की सहायता हेतु सरकार द्वारा 50ः की सब्सिडी दी जाती है जो कि मध्यम तालाब हेतु एक लाख चौदह हजार दो सौ ;1ए14ए200द्ध तथा लघु तालाब हेतु बावन हजार पाँच सौ रूपये ;52ए500द्ध निर्धारित की गयी अनुदान की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से तीन किस्तों में सीधे किसान के खाते में की जाती है तालाब खुदाई का कार्य कृषक की निजी भूमि पर ट्रैक्टरए जे0सी0बी0 मशीन या पुकलैंड मशीन के माध्यम से किसान द्वारा स्वयं कराया जाता है। खेत तालाब योजना का लाभ पिछले कई वर्षो से जनपद के किसान उठा रहे है जिससे किसानों की उत्पादकता में वृद्धि हो रही हैए योजना बुंदेलखण्ड क्षेत्र लिए वरदान साबित हो रही है।

मालिक.मुद्रक,प्रकाशक,संपादक ठाकुर दास प्रजापति द्वारा जयऑफ सेट प्रेस दीनदयाल मार्केट मिनर्वा चौराहा झांसी से मुद्रित एवं 469 नई बस्ती झाँसी से प्रकाशित **संपादक ठाकुरदास प्रजापति**(पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन हेतु जिमेदार सभी विवादों का न्याय क्षेत्र झाँसी न्यायालय के अधीन होगा । रजिस्ट्रेशन नं. यूपी एचआईएन /2015/ 64 737 फोन न. 6393149766,8005203626